

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 47/2020

तारीख रजू 28.01.2020

1. मुंशी बंजारा पुत्र कमाल जाति मुसलमान बंजारा निवासी ढाणी हसनपुरा कंवरपुरा (शिवाड़) तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कुलदीप 2. अनिल 3. कालूराम 4. मनीष पुत्रान डूंगरमल जाति कोली निवासीयान ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोजेण्ट्स

वकील अपीलान्ट्स-श्री अब्दुल वहाब
वकील रेस्पोजेण्ट्स-श्री सुधीर कुमार जैन

निर्णय दिनांक:- 03.08.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 06/2016 मे पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 हैक्ट० वाके ग्राम कंवरपुरा से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेण्ट की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अदालत मातहत में रेस्पोजेण्ट द्वारा एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आरटीएक्ट अपीलान्ट के विरुद्ध पेश किया जिस पर अपीलान्ट की तलबी की जाकर रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खिलाफ कानून जाकर 183 बी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश विधि तरीके से पारित कर दिये गये। यह है कि अदालत मातहत द्वारा पारित

निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ रूयेदाद मिसल होने की सूरत में काबिले निरस्त है। यह है कि अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया और न ही appreciate कर discuss किया और सरसरी तरीके से ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया। जो निरस्त होने योग्य है। यह है कि अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि वास्तविक रूप से किस व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिए था लेकिन एक तृतीय पक्षकार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के कारण वास्तविक पक्षकार की सुनवाई किये बिना ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह है कि वास्तविकता यह है कि साविक खसरा नम्बर 129 वाके ग्राम कंवरपुरा (शिवाड) काफी बड़झ रकबा था, में रेस्पोंडेन्ट प्रार्थीयान के पिता डूंगरमल पुत्र मांगीलाल कोली एवं नानगराम फतेहलाल पिसरान मांगीलाल कोली की 5-5 बीघा भूमि की खातेदारी थी लेकिन अभी हाल में हुए सेटिलमेंट के दौरान उक्त साविक खसरा नम्बर 129 से बने नवीन खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है० नानगराम फतेहलाल के नाम गलत खातेदारी अंकित कर दी जबकि डूंगरमल का नवीन खसरा नम्बर 568 पर व नानगराम फतेहलाल का नवीन खसरा नम्बर 571 पर कब्जा चला आ रहा है नानगराम फतेहलाल को सेटिलमेंट विभाग वालो के द्वारा की गई इस गलती की जानकारी हुई तो नानगराम फतेहलाल वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट मु०नं० 48/011 उनवानी नानगराम वगैरा बनाम डूंगरमल न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहां प्रस्तुत किया जिस पर मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा ने दिनांक 10.10.2014 को नानगराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि डूंगरमल पुत्र मांगीलाल कोली निवासी शिवाड के नाम दर्ज खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है० हजफ कर नानगराम, फतेहलाल, पन्नी, सीता शांति व शंकरलाल के नाम खसरा नं० 571 रकबा 1.26 है० भूमि खातेदारी दर्ज करने एवं खसरा नं० 568 रकबा 1.27 है० की खातेदारी डूंगरमल पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये लेकिन अदालत मातहत ने इस तथ्य के संबंध में कोई अवलोकन कर finding नहीं दी और सरसरी तरीके से ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो कि निरस्त होने योग्य है। यह कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा 136 एलआर एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट प्रार्थीगण ने माननीय संभागीय आयुक्त महो० रतपुर के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है जो इस समय विचाराधीन है जिसकी प्रति भी पीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रस्तुत कर दी परन्तु अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों को भी अपने निर्णय में कहीं अंकन नहीं किया इसलिए निर्णय जैरे बहस निरस्त होने योग्य है। यह नानगराम फतेहलाल कोली के नाम खसरा नम्बर 571 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने आदेश है लेकिन रेस्पोंडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त निर्णय का अंकन नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

साविक नं० 48/011

होने दिया जबकि नानगराम व फतेहलाल ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 अपीलान्ट को साझे बांटे पर काश्त हेतु बता रखी है तथा नानगराम वगैरा के आधार पर ही अपीलान्ट उक्त भूमि को साझे बांटे पर काश्त करता चला आ रहा है और इस समय अपीलान्ट की फसल सरसो खेत में सरसब्ज खड़ी हुई है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से फतेहलाल का शपथ पत्र भी अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया था परन्तु अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों का भी अपने निर्णय में कहीं भी अंकन नहीं किया और सरसरी तरीके से ही निर्णय जैसे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह कि नवीन खसरा नम्बर 571 पर रेस्पोजेन्ट प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है और न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा नवीन खसरा नम्बर 571 से रेस्पोजेन्ट प्रार्थीगण कुलदीप की खातेदारी से नाम हजक किए जाने के आदेश हो चुके हैं तो उनका खसरा नम्बर 571 से कोई संबंध या वास्ता नहीं रहा है लेकिन रेस्पोजेन्ट ने न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के निर्णय व अपील के तथ्यों को छिपाते हुए एक तृतीय पक्षकार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र 183(बी) आरटी एक्ट प्रस्तुत कर दिया जबकि नानगराम व फतेहलाल को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया जबकि वह आवश्यक पक्षकार है इसलिए बिना पक्षकार बनाये प्रा0पत्र चलने योग्य नहीं होते हुए भी निर्णय जैसे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अदालत मातहत ने निर्णय जैसे बहस अपीलान्ट से नाराज होकर पारित किया है जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अदालत मातहत का रीडर श्री नरेन्द्र वर्मा जो कि रेस्पोजेन्ट का दूर का रिश्तेदार है जो अदालत मातहत की कार्यवाही को प्रभावित कर रहा था इसलिए अपीलान्ट ने अदालत मातहत से पत्रावली मुन्तकिल करवाने हेतु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत किया जो निरस्त होने पर अदालत मातहत ने निर्णय जैसे बहस किया है जिसको उन्होंने अपने निर्णय में भी अंकन किया है इसलिए निर्णय जैसे बहस रंजिश रखते हुए पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि विवादित आराजी पर रेस्पोजेन्ट का कोई टाइटल नहीं है तथा प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के यहां विचाराधीन है जहां से प्रकरण का निस्तारण होना बाकी है लेकिन उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अदालत मातहत में प्रस्तुत कर दिय जाने के उपरान्त भी अदालत मातहत ने निर्णय जैसे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी 1 स्थित है जो रेस्पोजेन्ट्स को विरासत में मिली है इससे पूर्व रेस्पोजेन्ट्स के पिता डूंगरमल पुत्र मांगीलाल कोली की खातेदारी में थी डूंगरमल की मृत्यु के बाद यह आराजी नामान्तकरण सं. 155 निर्णय दिनांक 07.09.2015 द्वारा रेस्पोजेन्ट्स की खातेदारी में दर्ज हुई है। जमाबंदी सम्वंत 2071 से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

2074 के अनुसार ही हम खातेदार व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है० पर लट्ट के जोर पर जबरन कब्जा कर लिया था जिसके विरुद्ध रैस्पोजेन्ट्स के पिता ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर में दावा पेश किया था जिसमें दिनांक 19.01.2006 को प्रार्थी के पिता के हक में डिक्री कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की रैस्पोजेन्ट्स के पिता डूंगरमल ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर की अदालत में डिक्री की इजराय पेश की जिसमें तहसीलदार चौथ का बरवाडा को डिक्री का क्रियान्वयन करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में दिनांक 17.06.2006 को मौके पर रैस्पोजेन्ट्स के पिता को ख०न० 571 रकबा 1.26 है० वाके ग्राम कंवरपुरा का कब्जा संभलाया था। अपीलान्ट जो सवर्ण जाति का है के द्वारा रैस्पोजेन्ट्स की खातेदारी की भूमि ख०न० 571 रकबा 1.26 है० पर जबरन लट्ट के जोर पर कब्जा करने पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राज० टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत हमारे द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के यहाँ प्रस्तुत करने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 10.10.2014 को आदेश पारित कर उक्त विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है० पर जबरन कब्जा कर हडपना चाहते है। अंत में वकील रैस्पोजेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को विधि एवं नियमों के अनुसार सही पारित करना बताया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने बाबत निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रैस्पोजेन्ट्स कुलदीप वगै० द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी.एक्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है० पर अपीलार्थी ने लट्ट के जोर पर कब्जा कर लिया है जिसको पुलिस इमदाद द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा संभलाने बाबत निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 16/16 दिनांक 24.08.16 को दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर उभय पक्षों को बुला जाकर दिनांक 08.01.2020 को रैस्पोजेन्ट्स कुलदीप वगै० के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जाँच कराई गयी मुताबिक पर्चा मौका दिनांक 26.12.2016 के द्वारा पटवारी हल्का ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट में यह अंकित किया ख०न० 571 रकबा 1.26 है० वाके ग्राम कंवरपुरा कुलदीप, अनिल, कालूराम, मनीष पि. डूंगरमल सम्वती मैना पुत्रिया डूंगरमल जाति कोली के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 का अवलोकन करने पर भी पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि होती है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। जमाबन्दी, पटवारी रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि उक्त आराजी

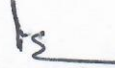
आरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांक 571 रकबा 1.26 है० अपीलान्त की खातेदारी है। अपीलान्त द्वारा दौराने बहस न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा मु०नं० 257/20 डूंगरमल बनाम नानगराम न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट में दिये गये निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में ऑडरशीट पर पारित निर्णय दिनांक 17.05.2022 की प्रतिलिपि पेश की है। अपीलान्त को न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त सवाईमाधोपुर के निर्णय की पालना बाबत् सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए।

न्यायालय हाजा में अपीलान्त द्वारा न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 08.01.2020 के विरुद्ध अपील पेश की है जिसके संबंध में अपीलान्त आराजी ख०नं० 571 रकबा 1.26 है० पर अपनी खातेदारी साबित करने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर